श्री गोविन्दराम मिरी: उपसभापति जी, प्रधानमंत्री जी को पेड़ लगाने चाहिये।

उपसभापतिः प्रधान मंत्री को ही क्यों, हम सबको मेड़ लगाने चाहिये। एक आदमी को नहीं बल्कि सबको लगाने चाहिये।

RE. DEMONSTRATION **BEFORE PARLIAMENT** BY ALL **INDIA** GRAMIN BANK **EMPLOYEES** AGAINST DISCRIMINATION AND DISPARITY IN WAGE STRUCTURE AND SERVICE CONDITIONS

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): पीठासीन हुए

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार)ः महोदय, मैं सदन में आल इंडिया प्रामीण बैंक वर्कर्ज एसोसिएशन और आल इंडिया ग्रामीण बैंक आफिसर्स एसोसिएशन के लोग जो दिल्ली में घरने पर बैठे हुए हैं, उनकी प्रमुख मांगों की ओर ध्यान दिलाना चाहुंगा। उनकी प्रमुख मांग यह है कि देश के सभी क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कैंक की स्थापना की जाये साथ ही बैंकिंग से छठे वेतन समझौते को प्रामीण बैंकों में भी लाग किया जाये। इन मांगों को लेकर ये दो संगठन आज दिल्ली में धरना दे रहे हैं। सवाल यह है कि ग्रामीण बैंकों को भी मजबूत किया जाना चाहिये। क्या हमारी सरकार सार्वजनिक षेत्र के अंदर जो बैंक हैं उन बैंकों को निजी क्षेत्र में देने का इरादा रखती है? इसी वजह से इनकी जो उदारीकरण की नीति है इस नीति के तहत बामीण निजी क्षेत्र में लोकल एरिया बैंक खोलने का ऐलान किया है। हम सब जानते हैं कि वे अप्रीण बैंक गांवों में गरीबों को, गरीब किसानों को, खेतीहर मजदूरों को कर्जा मुहैया करने में मदद करते हैं। और इनके माध्यम से सरकार जो गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं चला रही है उसके तहत उनको मदद मिलती है। यदि मान लिया जाये कि इन बैंकों में कुछ कमजोरिया है तो उनको दर कर इसे मजबूत बनाया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाये तो वित्त मंत्रालय और हमारी सरकार ने जो लोकल एरिया बैंक खोलने का ऐलान किया है उससे इस बात की मंशा जाहिर होती है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारे बैंक हैं उनको निजी क्षेत्र में ले जाना चाहती है। यही दो प्रमुख मांगे हैं जिनकी चर्चा मैंने सदन में की! इनकी मांग है कि सभी ग्रामीण बैंकों को और क्षेत्रीय बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाये। मैं समझता हं कि सदन की इस

मामलें पर सहमति होगी और इनकी बैंकिंग प्रणाली को मजबूती मिलेगी। साथ ही बैंकिंग उद्योग में जो छठा वेतन समझौता हुआ था उसको वित्त मंत्रालय की ओर से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन में हुई विसंगतियां दूर नहीं हो पा रही हैं। पेंशन की स्कीम में उनको जो मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। कम्प्यूटर के एलाउन्सेंज जो दूसरे डिपार्टमेंट में मिलते हैं वे भी उनको नहीं मिलते हैं। इस तरह से डिस्पेरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, और इससे सरकार दोहरी नीति पर बैंकों को ले जाना चाहती है। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से. आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहंगा कि ग्रामीण बैंकों में जो बैंकों का छठा वेतन समझौता हुआ था उसको लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय आवश्यक कदम उठाये ताकि उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। इन्हीं शस्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता है।

and Disparity in wage

Structure and service

tt.فتری وبلال/مرین(نعماری تبیار» : مبردے - میں معدن میں اول انٹریا ترامین وركم مس اليسيسى اليشن احدال ان ويا كوين بينك الميستدايسوس اليشن كوك جو وبلى مين وهي بريعين موسويمي التي مين مينكة ب م مع معند لم لكاحا نا چاسیهٔ-نیلهادی مسرکارسماروجنگ شیر کے اندوم بینک ہیں ان بینکوں ک نجى مشينز ميودين كادرا وه دموته

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल)ः माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जलालुदीन जी से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं इस सदन के सामने यह मांग रखना चाहंगी कि प्रामीण बैंकों को शहरों का जो पुअर कज़न माना जा रहा है, यह उचित नहीं है। भारत की उन्नति मुख्यतः ग्रामों की उन्नति पर निर्भर करती है। जो यह आंदोलन शुरू हुआ है, वे संसद तक मार्च कर रहे हैं और दूसरी यूनियने जो आल इंडिया रूरल बैंक्स एसोसियेशन है, उसके कर्मचारी भी कुछ दिनों के बाद आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उनकी

ا مى وجەسىعان ئى جوادارىيى كى ميں بوکل اير يا بينائک عکو لنے کا اعلان فربنا بانجانا جاسي - يدي يسا

Confirming India's Decision to

भी यही मांग है। मैं उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हए यह कहना चाहुंगा कि उनके लिए जो सविधायें अन्य स्पांसर बैंकों को मिल रही हैं, वह उनको भी मिलें और सिक्सथ बाइपार्टीइट वेज सेटलमेंट को लागू करने की व्यवस्था की जाए और प्राइस इंडेक्स लिंक्ट पेंशन स्कीम लागू की जाए। साथ ही उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए नये वेतनमान जरूदी से जल्दी लागू किए जाएं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रामीण बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी आज फिर से सदन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। साढ़े तीन साल पहले भी ये लोग यहां आए थे और उन्होंने धरना दिया था। उस समय जब लोकसभा में इस पर सवाल उठाए गए तो कई प्रमुख लोगों ने, जो आज सरकार में हैं या सरकार का सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया था। मैं नाम गिनाना नहीं चाहता, श्री चटजीं, श्री श्रीकांत जेना और श्री चाकु, और भी कई बड़े-बड़े नेता थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नेशनल रूरतः बैंक m rural areas can advance

beyond 40 per cent and would be a source of profit compared to the other commercial banks. Let them come forward with a Bill for establishing this

National Rural Bank of India. आज सरकार में यह लोग मोजूद हैं। आज दुबारा फिर से प्रामाण बेंक के सारे लोग यहां पर है। मैं चाहता हं कि सरकार की तरफ से आज यह घोषणा हो कि वह नेशनल रूरल वैंक्स के बारे में कब यहां बिल लाना चाहती है। अफसोस की बात है कि इसको पीछे डालकर लोकल बनाने की स्कीभ घोषित की गई है। अब लोकल परिया बैंक एक प्रकार से ऋमीण क्षेत्रों का पैसा निकालकर शहरी क्षेत्रों में लें जाकर अमा कर देंगे का वहां लगा देंगे। मैं समझता हूं कि इस लोकल एरिया बैंकों की कीम को खाल कर देना चाहिए अगर हम वास्तव में नेशनल रूरल बैंक आफ इंडिया को एस्टेबिलश करने के पक्ष में हैं।

दूसरी बात मेरी यह है कि 14 फरवरी, 1995 को बैंकिंग उद्योग ने छठा बेतन समझौता किया था। परन्तु प्रामीण बैकों में इसको लागू नहीं किया गया। तर्क दिया गया कि वहां घाटा हो रहा है। मैं सरकार के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि सार्वजनिक बैंक भी घाटे में क्ल रहे हैं। आगर उनके इम्पलाईज पर छटा वेदन आयोग का समझता लागू हो गया है तो आयीण बैंकों के कर्मचारियों पर यह लागू क्यों नहीं किया गया? मैं काहता हूं कि सरकार इ प्रश्न पर गंभीरता से विचार को और प्रामीण वैक के कर्मचारियों को भी छठे वेतन समझौते के अनुसार तरख्वाह और सुविधार्वे प्रदान करे। बहुत बहुत

श्री सोपपाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक महोदय, जो मुद्दा अभी माननीय पंडारी जी ने उठाया है, मैं भी सका समर्थन करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के व्यवस्था इतनी खरान है कि उसके जो कृषि इतर क्षेत्र हैं, उनके साथ ऋण देने में जो व्यवहार किया जाता है,

बैको द्वारा, सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा जमीन आसमान का अत्य है। प्रामीण क्षेत्रों में उसकी प्रक्रियांचे भी इतनी उदिल है कि उसका बहत विस्तृत विवरण है, उसके लिए ज्यादा समय चाहिये, इसलिए मैं आपका ज्यादा खराब नहीं करना चाहता है। मैं उनका समर्थन करना सहता हूं। पिछली सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में सारी बैंकिंग प्रभाली ने जितना ऋण विकास के लिए दिया, उसका केवल 13 या 14 प्रतिशत गांवों में दिया गया। अगर आए हनकी सी॰डी॰ रेश्यों देखें, जितना जमा होता है, जितना उसके बाद ऋण दिया जाता है, जितनी भी बैंकों की मामीण शाखाये हैं, उनकी सी॰डी॰ रेड़्यों खराब है और शहरों में और कृषि इतर क्षेत्रों में बहुत अच्छा है। कहीं कहीं तो यह 100 प्रतिस्तर के ऊपर 117, 137 प्रतिशत तक है। जमा रहिश गांवों की बांचे ज्यादा ले आती है और कर्ज उनके कथ दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने उनके लिए फेक्ल 18 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया था। ऐसा कोई राष्ट्रीयकृत बैंक कहीं है, एकाध को छोड़ कर, जिसने 18 प्रतिशत का लक्ष्य कभी किसी एक बिन्दु के ऊपर प्राप्त किया हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता है कि प्रामीण क्षेत्रों की ऋण ध्यवस्था को बिलकुल सुधरा और सुथरा रूप देने के लिए इन प्रामीण बैंकों का एक अलग ढांचा बनाए जाने की जो बात भंडारी जी ने कहीं है. उनकों क्रियान्वित अन्दें के तिए सरकार प्रभावी कदम उठाए। धन्यवाद।

REA REPORTED STATEMENT BY COMMERCE SECRETARY, CON-FIRMING INDIA'S DECISION TO UP-**GRADE INTELLECTUAL PROPERTY** RIGHTS IN ACCORDANCE WITH WORLD STANDARDS

BIPLAB DASGUPTA Bengal): Sir, while our Minister of Commerce is doing a commendable job in Singapore, at this moment, defending our position against the western governments' pressure to bring in labour standards, investment policies and all that, which we welcome. I find that from his department. certain other policies are enanating which are not in conformity with the position which this particular House has taken in the past or with the decisions declared by the Government in the past or even in terms of the Common Minimum Programme. I have nothing to say against a civil servant. I am assuming that the civil servant is speaking on behalf of the Government and is enunciating its policies. Shri Tejendra Khanna who is the Commerce Secretary has recently come out with a number of state ments. I am opposed to both the substance and the language used. For exam-